गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि, मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) महोदय, केन्द्रीय कपास अनुसंधान, संस्थान, नागपुर के दो क्षेत्रीय केन्द्र हैं जो सिरसा और कोयम्बटूर में स्थित हैं ।

(ख) , से (घ) क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए स्वीकृत स्टाफ और कार्यरत वैज्ञानिकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

केन्द्र	स्वीकृत स्टाफ की संख्या	कार्यरत वैज्ञानिक
कोयम्बतूर	25	18
सिरसा	13	06

भा.कृ. अनु. परिषद् में वैज्ञानिकों के खाली पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है जिन्हें विज्ञापित किया जाता है ।

(ङ) आनुपातिक संख्या में वैज्ञानिकों, तकनीकी, प्रशासकीय और सहायक कर्मचारियों, उपकरणों एवं सिंचाई सुविधाएं प्रदान कर उक्त दोनों क्षेत्रीय केन्द्रो को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए गए हैं । टेक्नोलाजी के विकास और मूल अध्ययन के लिए भी केन्द्रों में चल रहे कपास अनुसंधान कार्य को सम्मेकित किया गया है ।

विषय कृषि विज्ञान केन्द्र

2050. **श्री ईश दत्त यादव** : : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है देश में नये कृषि विज्ञान केन्द्र खोले गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इन केन्द्रों को कौन-कौन से स्थानों पर खोला गया है ;

(ग) अभी तक खोले गए कृषि विज्ञान केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के क्या मानदण्ड है ?

गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी हां । [देखिए परिशिष्ट 167, अनुषंग संख्या 27]

(ख) और (ग) सूची अनुपत्र में दी गयी है ।

(घ) नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अंतर्गत यह अनिवार्य है कि इसका कार्यान्वयन करने वाला संगठन कृषि विज्ञान केन्द्र के स्थान पर बिना किसी शुल्क के 50 एकड़ कृषि योग्य भूमि और अन्य नागरिक सुविधाएं जैसे पानी और बिजली उपलब्ध कराएं । फिर भी, ऐसे पिछड़े /पर्वतीय जिलों को वरीयता दी जाएगी जहां अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग रहते हैं ।

दिल्ली दुग्ध योजना का दिल्ली प्रशासन को सौंपा जाना

2059. **श्री धीरेन जे. शाह** : **श्री राम जेठ मलानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना का भावी संचालन दिल्ली प्रशासन को सौंपने का निर्णय अन्तिम रूप से ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ;

(ग) क्या यह सच है कि वर्ष 1990 में सरकारिया समिति ने यह सिफारिश की थी कि इस योजना को सहकारी क्षेत्र में संचालित किया जाना चाहिए , और

(घ) यदि हां, तो उक्त सिफारिश को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :– (क) और (ख) जी हां । सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना को यथाशीघ्र दिल्ली प्रशासन को सौंपने का निर्णय लिया है ।

(ग) जी, हां ।